POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–4 APRIL 2025 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।

email id: vote1957@gmail.com

USCIRF Downgrades India As A "Country of particular concern"

The USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) has again awarded India the category of a "country of particular concern". This means India treats its minority poorly. The USCIRF has arraigned India in the same line as 15 other countries including Afghanistan, Russia, China, Pakistan and Saudi Arabia.

Naturally such castigation would hurt the sentiment of the government which has criticized and damned the report on expected line as being biased, politically motivated and prejudiced.

But the the facts are glaring here. On daily basis hate speeches are hurled neglecting even the Apex Court orders, reign of bulldozers mostly against the minorities is well known.

The letting the turmoils continue in Manipur without any appreciable action being taken to control the situation, seeing temples beneath every mosques , invariably allowing the riotous atmosphere during religious festivities, identifying the minorities shops during Kanwariyas' route and in Kumbha or other melas, and then the love jihad, and on beef issues !

Are such instnaces not too much to relegate India in the unwanted category of nations ! Remaining in denial modes would not help India salvage its image !

Fraternity which is the hallmark of our Constitution and which has been prominently mentioned in our Constitution is the mantra that should be followed and adhered to have the idea of India intact !

संसद अध्यक्ष ने मुझे बोलने नहीं दिया - राहुल गांधी

राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) हैं, ने हाल ही में दावा किया है कि उन्हें स्पीकर ओम बिरला द्वारा भारतीय संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह मुद्दा 26 मार्च, 2025 को बजट सत्र के दौरान प्रमुखता से सामने आया। खास घटना तब हुई जब गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया, जिसके बाद गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया।

स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि सदस्यों, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, को संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से, विशेष रूप से एलओपी को इस मामले में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

पत्रकारों को प्रताड़ित करने का नायाब तरीका

असम में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट जमानत देता है। पर उस पत्रकार को रिहा करने के बजाय उसके खिलाफ दूसरा एफ आई आर दर्ज कराकर फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर से जमानत मिलने पर फिर एक तीसरा एफ आई आर दर्ज कर के फिर से उसे जेल में रखा जा सकता है।इस तरह से कानून को धता बताया जाता है।

थोड़े में बात ये है कि असम के एक कॉपरेटिव बैंक में अनियमितता को उजागर करने की कोशिश की थी पत्रकार ने तथा उस बैंक के डायरेक्टर स्वयं असम के मुख्यमंत्री है।

जहां पत्रकार प्रताड़ित हों वहां लोकतंत्र की बात क्या करना !

कवि और कॉमेडियन के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध

आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद तथा कवि इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा सत्ताधारियों के खिलाफ लिखी कविता से खफा गुजरात सरकार द्वारा दर्ज एफ आई आर को रद्द करते हुए निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किया :-

"व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा विचारों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक स्वस्थ सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। विचारों और मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और मतों का जवाब दूसरा दृष्टिकोण व्यक्त करके दिया जाना चाहिए।"

“भले ही बड़ी संख्या में लोग किसी अन्य के व्यक्त विचारों को नापसंद करें, उस व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। साहित्य, जिसमें कविता, नाटक, फिल्में, व्यंग्य और कला शामिल हैं, मानव जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं।“

वहीं आज मद्रास हाइकोर्ट ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी। कुणाल कामरा के पीछे महाराष्ट्र की पुलिस पीछे पड़ी हुई है ।कई एफ आई आर दर्ज हुए हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने एक कार्यक्रम में सत्ताधारियों के खिलाफ व्यंग्य किए थे।

अंग्रेजों के खिलाफ लिखने में भी लोग सहमे सहमे रहते थे, डरे डरे रहते थे। क्या उसी तरह का माहौल नहीं बन रहा है अपने 75 वर्षीय लोकतांत्रिक देश भारत में!

Anti-Pensioners Stance Of Central Governemnt

The Central government has recently got amendments to the Central Civil Services (Pension) Rules as part of the Finance Bill, passed b the both houses of the Parliament. This legislative action, titled "Validation of the Central Civil Services (Pension) Rules and Principles for Expenditure on Pension Liabilities from the Consolidated Fund of India," aims to update and formalize the pension framework for central government employees covered under the CCS (Pension) Rules.

This implies that Pension Revision on recommendations of the Cntral Pay Commissions could be very well denied to eisting pensioners.

महाराष्ट्र में "कानून के राज" का मजाक- महाराष्ट्र चला यूपी की चाल

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि बुलडोजर चलाना गलत है तथा व्यापक निर्देश दिए थे कि उचित नोटिस देकर ही किसी का आशियाना ध्वस्त करना चाहिए।पर सुप्रीम कोर्ट की किसे पड़ी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री खुल्लमखुल्ला बयान देते हैं कि हाल ही हुए नागपुर में दंगा फैलाने वाले दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच जाता है। नागपुर बेंच डिमोलिशन पर रोक लगाता है। पर बुलडोजर चलाने वाले आदेश आने के पहले ही घर गिराने का काम तमाम कर देते हैं।

नेपाल में राजशाही पुनर्स्थापित करने के लिए आंदोलन

लोकतंत्र तथा गणतंत्र के जमाने में नेपाल में राजशाही सार्थकों द्वारा राजतंत्र को बहाल करने की मांग कुछ अजीब नहीं लगती है !

नेपाल में सरकार समर्थक राजशाही समर्थकों के विरोध में मोर्चा खोल रहे हैं।

अर्थात छोटे से नेपाल में कोलाहल शुरू है !

जज के घर में पैसे !

"न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है" या "जज भी घुस लेकर फैसले लेते हैं" की बातें आम जनता में होती रही है। पर हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी ऐसा कुछ होता होगा इस पर विश्वास नहीं होता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगनेके पश्चात भररी रकम पाए जाने की खबर ने न्यायपालिका की पहले से ही घटती साख में और बट्टा लगा दिया है।

माननीय जज का स्थानांतरण कर दिया गया है तथा जजों की एक कमिटी जांच कर रही है ।

POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–4 APRIL 2025 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

पंजाब की "आप" सरकार को भी बुलडोजर भाया !

लगभग साल भर से आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों के कुछ संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन स्थल को खाली कराने के लिए पंजाब की आप सरकार ने बुलडोजर चलाया ।

आश्चर्य इस बात का है कि आंदोलनों से जन्मी "आप पार्टी" भी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जिनके लिए बीजेपी सरकारें जानी जाती हैं।

बातचीत का रास्ता था !

बुल्डोज़र बाबा ,बुल्डोज़र मामा , बुल्डोज़र दादा और आगे क्या !

यूपी के मुख्यमंत्री ने बुल्डोज़र बाबा की ख्याति प्राप्त की । बाद में मध्य प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री ने बुल्डोज़र मामा की डिग्री ली । गुजरात के मुख्यमंत्री को बुल्डोज़र दादा की पदवी मिल चुकी है । और अब शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन विभूतियों से प्रभावित लग रहे हैं। बुल्डोज़र चाचा या काका जैसी पदवी या कोई अन्य नाम से ये भी नवाजे जा सकते हैं।

आश्चर्य होता है कि जंगल राज के इस कृत्य से आम जनता भी भी खुश लगती है पर ये खुशी तभी तक रहती है जब तक ये खुद जंगल नीति से प्रभावित नहीं होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट बार बार ये स्पष्ट कर चुका है कि अभियुक्तों की ही नहीं आप दोषी पाए गए अपराधियों के घर भी इस तरह से नहीं गिरा सकते हैं। घर संविधान के मूलभूत अधिकार के रूप मे संविधान के आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश भी जारी किये हैं । पर सरकार चला रहे राजनीति खेलने वालों को नयायिक निर्देशों को भी धता बताने में महारत हासिल है। न्यायालय की अवमानना के कई मामले चल रहे हैं। यूपी में भी तथा कुछ अन्य जगहों पर भी । सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ प्रवचन नहीं , कार्रवाई करनी चाहिए । ऐसे मामलों का स्वत: संज्ञान लेकर जिम्मेवार सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों को जेल की सजा देनी चाहिए तथा पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए और ये रकम दोषी सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों के निजी संपाती से वसूलना चाहिए ।

जंगल राज की भी हद होने लगती है जब बुल्डोज़र जाति धरम देखकर चलने लगते हैं ।

यूपी के मेरठ में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े कर हत्या की ! महिला और प्रेमी गिरफ्तार !

ऐसी खौफनाक घटना भी घटित होती हैं।

पति के भोजन में नशीले पदार्थ मिला देना। पति का बेहोश हो जाना। पत्नी तथा उसके प्रेमी द्वारा पति के टुकड़े टुकड़े करना , 15 टुकड़े, तथा बॉडी को घर में ही एक प्लास्टिक के टैंक में रखकर ऊपर से सीमेंट डाल देना ताकि किसी को पता नहीं चले !

हत्या के बाद प्रेमी के साथ उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश की सैर प जाना। सैर से वापसी के बाद जब महिला की मां ने पूछा कि उसके पति कहां है तब महिला ने स्वीकार किया कि उनलोगों ने पति की हत्या की है। बाद में वे पुलिस स्टेशन जाती हैं जहां पुलिस महिला को गिरफ्तार कर लेती है।

हैदराबाद में दो महिला यूट्यूबर पत्रकार गिरफ्तार

हैदराबाद में आज तड़के दो महिला पत्रकारों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।उनके ऊपर आरोप है कि वे लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ अभद्र तथा मानहानिजनक वीडियो बना रहे थे ।वो भी वहां की विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर में।

सवाल है कि अचानक गिरफ्तार करने की जरूरत क्या आन पड़ी ! पुलिस का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि वे लोग झूठे अपमानजनक वीडियो बना रहे थे।

रिकॉर्ड - विहीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर कार्यरत एनसीआरबी (National Crime Record Bureau) अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वेबसाइट ncrb.gov.in पर भारत में घटित अपराधों की सांख्यिकी 2022 से ही अद्यतन नहीं की गई है। आज पूरे 2 साल के बाद भी रिकॉर्ड्स इकट्ठा नहीं कर पाना सरकार की अक्षमता है या ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि जानकारियां सरकारों की आलोचना का कारण बन जाती हैं। इसलिए बहुत संभव है कि आलोचनाओं से बचने के लिए सरकारें अंधेरा कायम रखना चाहती हैं।

आज डिजिटल जमाने में सांख्यिकी (Data) तत्क्षण (instant) उपलब्ध कराए जा सकते हैं यदि इच्छा हो तो !

याद कीजिए किस तरह से भारत सरकार ने गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत करोड़ों या अरबों रुपए दान करने वाले दाताओं के नाम तथा दान पाने वाली राजनीतिक पार्टियों के नाम नहीं बताना चाहती थी।सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डांट पिलानी पड़ी तब जाकर लाभार्थियों तथा दानियों के लिस्ट उजागर किए गए थे।

लोकसभा में दिए गए मंत्री जी का जवाब विलंब को उचित ठहराने वाला लगता है। जवाब अड़ियल सरकारी कर्मियों द्वारा दिए जाने वाले जवाबों जैसा दिखता है।

Killings Continue In Chhatisgarh

Zero tolerance to unlawful activities is ok but is Gandhi ji's tool of non-violence getting irrelevant in today's world ! Is there not any other peaceful means to tackle the menace !

Violent means are ongoing in Gaza by Israel, by Russia in Ukrain, by America in Yemen and by India in Chhatisgarh !

I hold the view that along with strong-arm-tactics, the persuasive humanitarian approaches should not be lost sight of , altogether !

केंद्र सरकार कुंभ मेला में मरे हताहतों से अनभिज्ञ !*

केंद्र सरकार के पास कुंभ मेला के भगदड़ में मृतकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ये बात लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कही। उन्होंने संविधान की सातवीं सूची का हवाला देते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है जिससे केंद्र का कोई लेना देना नहीं है।

ये टालमटोल करने वाले सरकारी नौकरों द्वारा दिए जाने वाले जवाबों जैसा जवाब लगता है।

माना कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन का मसाला होता है। पर इतनी गंभीर बातों की जानकारी क्या केंद्रीय गृह विभाग उत्तर प्रदेश के राज्य के गृह विभाग से इस तरह की जानकारी हासिल नहीं कर सकता है !

इस तरह की जानकारी हासिल करने का अधिकार तो भारत के आम नागरिकों को हासिल है सूचना के अधिकार के अंदर । तो क्या भारत के सांसद इस तरह की जानकारी अधिकृत तौर पर मंत्रियों से नहीं ले सकते है !

इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए !

ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर देंगे

राजद नेता तथा पूर्वमंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने तो हद कर दी। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड पुलिस कर्मी को ये फरमान दिए। यद्यपि "बुरा ना मानो होली है" कह कर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश भी की।होली के दिन बिहार में भांग खाने को बुरा नहीं माना जाता है। लोग शराब या अन्य नशा भी करते हैं। और नशे में धूत होकर लोग अक्सर कुछ भी बोल जाते हैं।

सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को इस तरह की बातों से बचना चाहिए ! और चूंकि घटना पुलिसकर्मी के साथ घटित हुई है इसकी पुलिसिया जांच तथा कार्रवाई भी होनी चाहिए।

POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–4 APRIL 2025 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रंप को फटकार लगाई!

ज्ञातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन जजों के प्रति धृष्टता दिखाते है, जो उनकी नीतियों के खिलाफ फैसला देते हैं। वे खुलेआम कहते हैं कि ऐसे जजों को हटा देना चाहिए। ये या वे ओबामा के जज हैं !

ऐसी रवैया के खिलाफ अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश का बयान आया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यहां कोई ओबामा जज या ट्रंप जज या बुश जज या क्लिंटन जज नहीं है । उन्होंने कहा कि अमेरिका के 200 वर्षों का न्यायपालिका का इतिहास है जो समानता तथा न्याय पर आधारित है। फैसलों के खिलाफ जाने के न्यायिक विकल्पों जैसे अपील आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए , ना कि जजों के खिलाफ इस तरह के बयान देना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका का हमें कृतज्ञ होना चाहिए।

मस्जिद और मजार

पहले बाबर की मस्जिद को लेकर और अब औरंगजेब की मजार (Tomb) को लेकर माहौल तैयार किया जा रहा है।

अपेक्षाकृत शांति के लिए जाने जाने वाले नागपुर में तनाव पैदा करने की कोशिश चिंताजनक है। नागपुर की पब्लिक तथा पुलिस तथा प्रशासन ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया क्योंकि हताहत की कोई खबर नहीं है यद्यपि कुछ पुलिसकर्मियों को भी पथराव में चोट आई है।

अभी कुछ समय पहले तक मस्जिदों के नीचे मंदिरों के होने की बात हो रही थी/है।

सत्तापक्ष की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इच्छा के बगैर दंगे फसादों का होना संभव नहीं है। उत्तेजक बयान या भाषण आग में घी का काम करते हैं। इससे सबको , विशेषकर नेताओं को बचना चाहिए।

संविधान की प्रस्तावना में अंकित भाईचारा यानी बंधुत्व की भावना को आत्मसात करना सबका कर्तव्य है !

गुंडाराज के आगाज

बिहार में दो दिनों में दो पुलिसकर्मियों की हत्या

बिहार के अररिया तथा मुंगेर में एक के बाद एक महज दो दिनों के अंतराल में दो पुलिस सब इंस्पेक्टरों की हत्या बिहार की पुरानी छबि की याद दिलाती हैं।

सरल प्रश्न है कि जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं हैं वहां आम आदमी की हालत क्या होगी !

ये दोनों ही पुलिसकर्मी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मनचले या मनबढ़े गुंडा तत्वों ने इनकी जान ले ली।

पहली घटना बिहार के अररिया जिले के एक गांव की है जहां एक बारात में पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन मल की जान गई।

दूसरी घटना बिहार के मुंगेर जिले की है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह को फोन पर नंदलालपुर एरिया में एक परिवार द्वारा अशांति फैलाए जाने की खबर मिली। वे वारदात की जगह पहुंच कर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नशे में धूत बदमाशों ने उन पर किसी नुकीले चीज से हमला कर दिया । वे बुरी तरह घायल हो गए ।

उन्हें लोकल अस्पताल में दिखाया गया। बाद में पटना एक अस्पताल में ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका।

कानून की अव्यवस्था के लिए जाने जाने वाले बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि में धब्बा लगने जैसी बात है। वे स्वयं गृह मंत्री भी हैं। इसलिए कमियां व्यक्तिगत रूप से उनकी अक्षमता से जोड़ी जाएंगी। दोषियों को शीघ्रातिशीघ्र कानून सम्मत कठोरतम दंड दिलाना चाहिए ताकि इस तरह के अपराधों की पुनरावृति ना हो !

अमेरिका अधिनायकवादी चपेट में

ट्रंप के अधीन अमेरिका अधिनायकवादी उथल पुथल की ओर अग्रसर प्रतीत हो रहा है। नाटक जाना पहचाना है। अधिनायकवादी उदारवादी लोकतंत्र का फायदा लेकर , इसकी छोटी मोटी खामियों का उपयोग करके पूरे जनादेश के साथ सत्ता में आते हैं। फिर उसी उदारवादी लोकतंत्र को खोखला करने में लग जाते हैं ।

ये मौजूदा उदार व्यवस्था की आलोचना में छोटे-छोटे सच के दाने का उपयोग कर पूर्ण क्रांति के दावों को उचित ठहराने लगते हैं। ये एक या दो फोड़े फुंसी को पूरे चेहरे को काटने के लिए तर्क के रूप में उपयोग करते हैं।

ये उसी लोकतंत्र के रूप और संरचनाओं का उपयोग उसी उदार लोकतंत्र की मूल भावना को बिगाड़ने के लिए करते हैं।

ये अंदर से पक्के अधिनायकवादी होते हैं। यह हर उपलब्ध साधन का उपयोग तथा राष्ट्रीय हित के हर कार्ड का प्रयोग करके स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर काबू पाने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं।

शासन पीड़िता के मंत्र को पहनता है - यह खुद को राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार बताता है। इससे राजनीतिक विरोधियों को धमकाने का लाइसेंस मिलता है।

ये विरोधी दलों की रोकथाम के लिए लोकतंत्र में कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा संतुलन बनाए रखने के प्रावधानों को अभिजात वर्ग का हथकंडा बताकर कमजोर करने को वैधता प्रदान करते हैं । उदाहरण के लिए, उनके रास्ते में आने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाना या उससे भी बदतर कार्रवाई करना।

ये नियम कानूनों के प्रति नहीं , खुद के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा की अपेक्षा करते हैं।

(साभार :- 18 मार्च 2025 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित प्रताप भानु मेहता के अंग्रेजी लेख के कुछ अंश का हिन्दी में रूपांतरण के साथ अपने विचार रखने का प्रयास। विस्तार से तथा सत्यता (authenticity) के लिए लेखक के लेख को पढ़ना होगा।)

Progressive Raj Thackeray !

At last we got someone amongst politicians in India who is candid and so much forthright to tell the whole world his views on Kumbh and taking bath in Ganga. This is unlike other politicians who don't speak out for fear of losing votes in the votebank politics in India. MNS chief Raj Thackeray could be so progressive and liberal is a surprise to me and I really appreciate it.

This is worth for other politicians in India to emulate MNS chief Raj Thackeray , at least , in this particular respect !

प्रेस पर पाबंदी

महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का एक मीडिया सेंटर बनाने का फैसला लिया है जो मीडिया - प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि पर नजर रखेगा कि कौन सा न्यूज सकारात्मक (positive)है कौन सा नकारात्मक (negative) है या भ्रमात्मक है।

अब ये लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा समाचार सकारात्मक है तथा कौन सा नकारात्मक या कौन सा भ्रमात्मक !

मतलब साफ है कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रेस अर्थात मीडिया को कैसे वश में किया जाय इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया जाएगा दंडात्मक कार्रवाई होगी।

भारत वैसे ही विश्व पटल पर प्रेस की आजादी के माने में 142 वें सूचकांक पर है। महाराष्ट्र सरकार के ऐसे फैसले प्रेस की आजादी को और नीचे ले जाएगा।मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ होता है। अत: मीडिया पर नियंत्रण लोकतंत्र पर नियंत्रण है। भारत की गोदी मीडिया पहले से ही लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। अब सरकारें विधिवत मीडिया को नष्ट करने का उपाय कर रही हैं जिसमे महाराष्ट्र अग्रणी बन रहा है !

POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–4 APRIL 2025 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

This is what GROK said about the contribution of RSS in India's freedom movement

The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), founded in 1925 by Keshav Baliram Hedgewar, is often a subject of debate when it comes to its role in India's freedom movement against British colonial rule. Unlike the Indian National Congress or the Communist Party, the RSS did not prioritize direct confrontation with the British as its primary objective. Instead, it focused on nation-building through cultural revival, Hindu unity, and grassroots organization, which its supporters argue indirectly bolstered the broader independence struggle, while critics contend it remained largely aloof from active anti-colonial resistance.

Hedgewar, a former Congress member influenced by revolutionary ideas, established the RSS to strengthen Hindu society, which he saw as fragmented and weakened under colonial rule. The organization emphasized physical training, discipline, and ideological indoctrination through shakhas (local branches), aiming to create a cadre of disciplined volunteers (swayamsevaks) for national service. This approach stemmed from Hedgewar's belief that independence required a strong, united societal base rather than just political agitation—a long-term vision rather than immediate activism.

The RSS's direct participation in the freedom movement was limited. It did not organize mass protests, strikes, or armed revolts against the British, unlike the Congress or revolutionary groups. Historical records show Hedgewar discouraging RSS members from joining the Civil Disobedience Movement of 1930–32, arguing that such actions diverted energy from organizational growth. During the Quit India Movement of 1942, when the Congress launched a mass uprising, the RSS under M.S. Golwalkar (who succeeded Hedgewar in 1940) maintained a low profile, with Golwalkar reportedly advising swayamsevaks to avoid confrontation with the British. British intelligence reports from the period, such as those cited in historian P.B. Sinha's works, note the RSS's minimal anti-government activity, and the organization was never banned by the colonial authorities during the freedom struggle—a contrast to groups like the CPI or Congress.

However, RSS supporters highlight individual contributions. Many swayamsevaks participated in the freedom movement in personal capacities, often through Congress-led campaigns or revolutionary outfits. For instance, Nathuram Godse (later infamous for assassinating Gandhi) and Narayan Apte, both early RSS members, were involved in nationalist activities before drifting toward extremism. Hedgewar himself had been active in revolutionary circles in his pre-RSS days, including the Anushilan Samiti, and was jailed during the 1920s for Congress work. The RSS also claims it provided a support network during emergencies, such as aiding Congress workers underground during Quit India, though evidence of this is anecdotal and not well-documented.

Critics, including historians like A.G. Noorani, argue that the RSS's ideological focus on Hindu nationalism distanced it from the inclusive, secular thrust of the mainstream freedom movement. Golwalkar's writings in We or Our Nationhood Defined (1939), emphasizing a Hindu Rashtra, clashed with the Congress's vision of a pluralistic India, creating ideological friction. The RSS's abstention from mass movements is often cited as evidence of its limited contribution to ousting the British, with some alleging it prioritized organizational survival over national liberation.

Post-independence, the RSS has framed its role as a silent, foundational force, claiming its efforts in fostering national pride and unity among Hindus indirectly fueled the freedom struggle's momentum. Its defenders point to its rapid growth—by 1947, it had thousands of shakhas—as evidence of mobilizing national consciousness. Yet, mainstream historical accounts, such as those by Bipan Chandra, give it little credit for directly hastening independence, focusing instead on its post-1947 influence.

In essence, the RSS's contribution to India's freedom movement was indirect and organizational rather than confrontational. It built a disciplined cadre and promoted a nationalist ethos rooted in Hindu identity, which it argues strengthened the societal fabric for independence. However, its reluctance to engage in active resistance against the British, coupled with its focus on long-term cultural goals over immediate political action, leaves its role in the freedom struggle as a polarizing topic—celebrated by its adherents as a quiet force, but often dismissed by others as peripheral to the fight that won India's liberty.

This is what GROK said about the contribution of Indian Communists in India's freedom movement

Indian Communists played a significant, though often understated, role in India's freedom movement against British colonial rule. Their contributions were marked by a blend of revolutionary zeal, organizational efforts, and a focus on mobilizing the working class and peasantry, often in alignment with broader nationalist goals, though their ideological leanings sometimes put them at odds with mainstream nationalist leaders.

The Communist Party of India (CPI) was formally established in 1925, though communist ideas had begun percolating earlier through individuals influenced by the Bolshevik Revolution of 1917. Early figures like M.N. Roy, who co-founded the CPI, were instrumental in linking Indian anti-colonialism with global socialist movements. Roy, initially a nationalist revolutionary, turned to Marxism and worked to establish communist networks in India, even collaborating with the Comintern (Communist International) to strategize against British imperialism.

One of the Communists' key contributions was their focus on organizing the proletariat and peasantry, groups often sidelined by the elite-led Indian National Congress. In the 1920s and 1930s, they were active in labor movements, leading strikes and forming trade unions. The Bombay textile workers' strike of 1928, led by communists like S.A. Dange and K.N. Joglekar, was a landmark event, showcasing their ability to mobilize industrial workers against both British exploitation and Indian mill owners. This emphasis on class struggle added a radical edge to the freedom movement, pushing economic justice alongside political independence.

Communists also participated in revolutionary activities. The Meerut Conspiracy Case of 1929, where British authorities arrested 31 communist leaders including Muzaffar Ahmed and P.C. Joshi, highlighted their growing influence and the threat they posed to colonial rule. Though the trial aimed to suppress them, it inadvertently amplified their message, as the accused used the courtroom to articulate their anti-imperialist stance.

During the 1930s, the CPI aligned intermittently with the Congress, especially under the Popular Front strategy dictated by the Comintern to unite against fascism and imperialism. Communist leaders like P. Krishna Pillai in Kerala and A.K. Gopalan bolstered peasant movements, such as the Malabar agrarian struggles, tying local grievances to the national fight. However, their relationship with the Congress soured during World War II. In 1941, after the Soviet Union joined the Allies, the CPI supported the British war effort, branding it a "People's War" against fascism, which clashed with the Congress's Quit India Movement of 1942. This stance alienated them from mainstream nationalists and led to accusations of compromising the freedom struggle.

Despite this, Communists regrouped post-war and contributed to late-stage anti-colonial efforts. The Tebhaga movement (1946–47) in Bengal, where sharecroppers demanded a greater share of the harvest, and the Telangana armed struggle (1946–51) against feudal landlords and the Nizam of Hyderabad, demonstrated their commitment to radical change, even as India neared independence. These movements, while not directly causing British withdrawal, weakened the socio-economic structures supporting colonial rule.

In summary, Indian Communists enriched the freedom movement by amplifying the voices of workers and peasants, engaging in both armed and unarmed resistance, and injecting a class-based critique of imperialism. Their legacy, however, remains complex due to ideological splits, tactical missteps like the WWII stance, and their marginalization in post-independence narratives dominated by the Congress and other nationalist groups. Their impact lies not just in hastening independence but in shaping the discourse on equity and justice within the struggle.

Happy Gudi Padwa, Ugadi, Chaitra Navaratri, Puthandu, Cheti Chand, Navreh, Sajibu Nongma Panba, Eid Mubarak

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995